

संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम : पं० दीन दयाल उपाध्याय जागृति समिति ।
2. समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष ।
3. कार्यालय : 43 न्यू चौगुर्जी, इटावा ।
4. समिति के सदस्य : सदस्य चार प्रकार के होंगे :-

- (अ) संरक्षक सदस्य
- (ब) नामित सदस्य
- (स) आजीवन सदस्य
- (द) सम्मानित सदस्य
- (य) साधारण सदस्य

(अ) संरक्षक सदस्य

1. ये आजीवन सदस्य होंगे ।
2. योजनाओं को साकार कराने में अपना पूरा योगदान देंगे ।
3. इस तरह के दो संरक्षक सदस्य होंगे । वे स्थायी होंगे ।

(a) श्री सुमित नारायण तिवारी

(b) श्री प्रमोद दुवे

4. इनकी मृत्यु पर या नाम वापस लेने पर इनके द्वारा नामित या इनके परिवार का सदस्य ही पुनः संरक्षक सदस्य होगा ।

(ब) नामित सदस्य

जो संस्था इस समिति द्वारा संचालित संस्था या कार्यक्रमों में बृहद सहयोग करेगी उनका एक एक प्रतिनिधि नामित सदस्य होगा ।

अधिकार एवं कार्य क्षेत्र

1. नामित सदस्य संस्था के लिए अपने सुधारात्मक सुझाव देंगे, उन्हें प्रबन्धकार्यकारिणी द्वारा बहुमत के आधार पर लागू कराने का पूरा प्रयास किया जायेगा ।
2. वार्षिक प्रबन्ध कार्यकारिणी में बुलावा आवश्यक होगा ।
3. इस प्रकार के नामित सदस्यों द्वारा भेजे गये छात्रों के प्रवेश में शिथिलता दी जायेगी ।
4. परन्तु ये सदस्य न तो हानि लाभ में भागीदार होंगे और न ही प्रबन्ध कार्यकारिणी के चुनाव में भाग लेंगे ।

(स) आजीवन सदस्य:-

निम्न आजीवन सदस्य होंगे :-

1. वह जो एक लाख व इससे अधिक धन संस्था को देंगे या एक लाख रुपये व अधिक धन की सम्पत्ति संस्था के नाम करेंगे ।

सदस्य-प्रतिनिधि

2. इनकी संख्या अधिक से अधिक 30 तक होगी तथा कम से कम 20 होगी।
आजीवन सदस्यों का कार्य क्षेत्र अधिकार
कार्य क्षेत्र

1. आजीवन सदस्यों की समिति होगी जो प्रबन्ध समिति कहलायेगी।
2. इस समिति से ही संस्था के लिए निदेशक, उपनिदेशक, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष आदि का चुनाव होगा। उपनिदेशक विभाग के अनुसार कई हो सकते हैं। प्रत्येक विभाग में एक ही उप निदेशक होगा।
3. सभी पदों के लिए चुनाव का अधिकार इन सदस्यों का होगा।
4. जो सदस्य आजीवन सदस्य है वह प्रत्येक निदेशक, उपनिदेशक, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष, मुख्य अनुशासक आदि का चुनाव 5 साल पूरे होने पर अथवा अविश्वास प्रस्ताव आने पर करेगा।
5. एक मुख्य अनुशासक होगा। जिसका चुनाव प्रत्येक 5 साल में आजीवन सदस्यों में से ही होगा।
6. निदेशक की अनुपस्थिति में पूर्ण अधिकार निदेशक द्वारा नामित उपनिदेशक के होंगे लेकिन कोई उपनिदेशक एक साथ दो से अधिक बार नामित नहीं किया जा सकेगा।

अधिकार :-

1. केवल सभी आजीवन सदस्यों को ही प्रबन्ध समिति चुनने का अधिकार होगा।
2. सभी आजीवन सदस्य संस्था के लाभ-हानि दोनों धन देने के अनुपात में जिम्मेदार होंगे।
3. वशर्त वह योग्य हो।
4. आजीवन सदस्य को संस्था के हित में जो दायित्व सौंपा जायेगा उनमें जो खर्च आयेंगा वह प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत होने पर भुगतान किया जायेगा।
5. प्रत्येक खर्च को प्रबन्ध समिति में रखना होगा। जो कम से कम सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थन होने पर ही भुगतान होगा।
6. आजीवन सदस्यों की मृत्यु अथवा पृथक् होने की स्थिति में अन्य नया सदस्य सहमति से बनाया जायेगा। यदि मृतक आश्रित सदस्य बनना चाहे तो वह सदस्य बन सकता है। वशर्त वह पागल, अमर्यादित न हो। सभी आजीवन सदस्य बहुमत से उस नये सदस्य का चुनाव करेंगे। यदि मृतक आश्रित सदस्य अयोग्य है तो उसका धन जो संस्था को दिया गया था वापस कर दिया जायेगा।



निदेशक का कार्य क्षेत्र व अधिकार

1. शिक्षा को उत्तम बनाने के उद्देश्य से बनायी गयी विभिन्न समितियों की अध्यक्षता कराना।
2. जिस प्रस्ताव को अनुचित समझे उसे अस्वीकृत करके पुनः विचार हेतु प्रबन्ध समिति में रखना और विवाद होने की दशा में 1/2 से अधिक बहुमत से पारित कर पास कराना।

प्रतिपाद्य
1/A
R.K. S. C.
MK

सत्य-प्रतिलिपि

गोपनीय
संस्थापक समिति
उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी

Handwritten signature

निदेशक
उत्तर प्रदेश साहित्य अकादमी
मु. गुरुजी-समिति

3. संस्था के हित में प्रबन्ध समिति की बैठक थोड़े समय में (24 घण्टे में) बुलाने का अधिकार होगा।
4. पदाधिकारियों की अनियमितताओं को प्रबन्ध समिति में रखने का अधिकार।
5. कर्मचारियों के वेतन का भुगतान स्वीकृत करने का अधिकार। वेतन पहले कोषाधिकार अथवा उप कोषाधिकार से पास होना चाहिए।
6. अनुशासन समिति का अध्यक्ष। इससे सम्बन्धित सभी निर्णय लेने का अधिकार।
7. प्रवेश सम्बन्धी अनियमितताओं को रोकने सम्बन्धी अधिकार।
8. अधिक से अधिक आवश्यकता पड़ने पर 6 माह के लिए चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखने का अधिकार। इसकी स्वीकृति बाद में प्रबन्ध समिति से लेनी होगी।
9. सभी कर्मचारियों की छुट्टियों को स्वीकृत करने का अधिकार।
10. सभी विभागों के उपनिदेशक, कोषाध्यक्ष, उपकोषाध्यक्ष, तथा मुख्य अनुशासक के कार्यों को देखने व सुधार के लिए सुझाव देने का अधिकार जो सभी को मानना होगा। विवाद होने पर प्रबन्ध समिति में पास कराना जो 1/2 से अधिक बहुमत से पास होना चाहिए।
11. प्रबन्ध समिति के बिना अनुमति के 20,000.00 रुपये तक संस्थान हित में व्यय करने का अधिकार। परन्तु उस व्यय को बैठक में रखकर पास कराना अनिवार्य होगा। वर्ष में इससे अधिक खर्च करने की स्थिति में प्रबन्ध समिति बुलानी होगी।
12. सभी अनुदान, आय व्यय का ब्यौरा कोषाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत करने पर अपनी अन्तिम स्वीकृति देने का अधिकार।
13. किसी कारण से रिक्त हुए पद या नये पदों को भरने के लिए प्रस्ताव प्रबन्ध समिति में लाना व 1/2 से अधिक बहुमत से पास कराकर लागू करना।
14. प्रबन्ध समिति के अनुसार सभी धन सम्पत्ति की रक्षा करना।

उपनिदेशक के कार्य व अधिकार

1. निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक के कार्य को देखना।
2. अपने अपने विभाग की प्रवेश सम्बन्धी, अनुशासन सम्बन्धी, अनुदान सम्बन्धी, व व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी का ब्यौरा बनवाना तथा कमियों को दूर करने के लिए निदेशक से बैठक बुलाने का अधिकार।
3. अपने अपने विभाग का कार्य सम्बन्धित अध्यापक या कर्मचारियों से कराने का अधिकार।
4. सम्बन्धित विभाग के कर्मचारियों को अनियमितताओं के ऊपर नोटिस देने का अधिकार। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की अनियमितताओं पर दूसरे नोटिस के बाद नौकरी से निकलने का अधिकार।



प्रो. व. कुमार
V.A.
K.S.
M.

साक्ष्य-प्रतिलिपि

प्रमुख निदेशक
मुख्य निदेशक
मुख्य निदेशक

निदेशक
मुख्य निदेशक
मुख्य निदेशक

5. अपने विभाग की चल अचल सम्पत्ति का अवलोकन प्रत्येक सत्र में विभाग के कर्मचारियों से गौणने का अधिकार । जिससे प्रबन्ध समिति की बैठक में प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत करना होगा ।
6. प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था जैसे-पुस्तकालय , सफाई , विजली , जल , शिक्षा स्तर , आदि को सुधारने के लिए अपने विभागीय कर्मचारियों को निर्देशित करने का अधिकार , विवाद की स्थिति में निदेशक से मिलकर उचित स्थिति लागू करनी होगी ।
7. आय व्यय का व्यौरा कोषाध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष देना होगा ।

कोषाध्यक्ष , उपकोषाध्यक्ष के कार्य व अधिकार

1. संस्था के लिए सभी प्रकार के दान , अनुदान , चन्दे , सदस्यता शुल्क एवं सभी प्रकार के शुल्क आदि प्राप्त करना और उनका व्यौरा रखना ।
2. शिक्षा शुल्क व विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त सभी शुल्क का व्यौरा रखना तथा सम्बन्धित उप निदेशक से व्यौरा मांगने का अधिकार ।
3. सभी प्रकार की आय व्यय का लेखा जोखा रखना ।
4. संस्था की आर्थिक स्थिति पर नियंत्रण रखना और सुचारु रूप से चलाना ।
5. कर्मचारियों के वेतन का भुगतान स्वीकृत करना । संस्था के लिए आवश्यक सामान बजट के अनुसार उपलब्ध करना जिसके लिए 1/2 से अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक है ।
6. निदेशक , उपनिदेशक के द्वारा आवश्यक कार्य , आय व्यय निदेशक , उप निदेशक से मांगना तथा मीटिंग होने पर उसे प्रस्तुत करना ।
7. वाहन खरीदना व उसके खर्च के लिए आवश्यक धन का व्यौरा प्रबन्ध समिति द्वारा समय समय पर पास कराना जिसके लिए 1/2 से अधिक सदस्यों का बहुमत आवश्यक है ।
8. उपकोषाध्यक्ष का कार्य कोषाध्यक्ष का सहयोग करना ।
9. कोषाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारे काम उपकोषाध्यक्ष को करने होंगे ।



मुख्य अनुशासक : कार्य व अधिकार

1. संस्था में अनुशासन बनाये रखना ।
2. छात्र / छात्राओं की समस्याओं को सुनना तथा उनका समय समय पर निदान कराना ।
3. अपनी सुविधा के लिए सम्बन्धित अध्यापक से कार्य लेना जो संस्था के लिए ही होना चाहिए ।
4. छात्रावास की सारी व्यवस्थाओं को व सुविधाओं को उपलब्ध कराना ।
5. छात्र/छात्रा के स्वारण सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराना ।
6. खेल सम्बन्धी व्यवस्थाओं को पूरा करना ।

प्रमोद कुमार
VA
R/S
KK

सत्य-प्रतिलिपि

Signature

पुस्तकालय, उद्योग कोषाध्यक्ष समिति
मुख्य कोषाध्यक्ष

मुख्य अनुशासक
मुख्य कोषाध्यक्ष

7. छात्र/छात्राओं के लडाईं, झगडा को सुलझाना अधिक विवाद होने पर प्रबन्ध समिति में विषय रखकर छात्र/छात्रा को दण्ड दिलाना ।
निदेशक तथा मुख्य अनुशासक जो कि संस्था में आजीवन सदस्य है । जब तक पद पर रहेगे तब तक अपना पूरा समय संस्था को देने के कारण वार्षिक भत्ता लेने के हकदार होंगे । जो भत्ता प्रबन्ध समिति द्वारा प्रतिवर्ष तय किया जायेगा । जो उप निदेशक, निदेशक, मुख्य अनुशासक के स्थान पर कार्य करेंगे । उनको वही भत्ता जितने दिन वह कार्य करेंगे उसी के अनुपात में निदेशक व मुख्य निदेशक के खाते से काट कर दिया जायेगा ।

(द) सम्मानवीय सदस्य:- निम्न सम्मानवीय सदस्य होंगे:-

1. जो संस्था को रूपा 50000 से अधिक की चल या अचल सम्पत्ति प्रदान करेंगे वह सम्मानवीय सदस्य होंगे ।
2. इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है ।

सम्मानवीय सदस्यों का कार्यक्षेत्र व अधिकार:-

1. इनको संस्था के हित में सहयोग, सुझाव देने का पूरा अधिकार है । इनका सुझाव प्रबन्धसमिति की बैठक में रखा जायेगा बहुमत (2/3 सदस्य) होने पर लागू किया जायेगा ।
2. इनको संस्था का आय व्यय व्योरा लेने का अधिकार है अनियमितता पकड में आने पर प्रबन्ध समिति द्वारा उचित निर्णय किया जायेगा ।
3. जो सदस्य 50000 रुपये या अधिक की सम्पत्ति या रुपये संस्था को देंगे उन्हें प्रबन्धसमिति में न तो वोट डालने का अधिकार होगा और न किसी पद पर खडे होने का अधिकार होगा ।
4. आजीवन सदस्य की मृत्यु के बाद अथवा अपना नाम वापस लेने के बाद यदि कोई सम्मानवीय सदस्य आजीवन सदस्य बनना चाहता है । तो वह 60000 य0 पुनः जमा करके आजीवन सदस्य बन सकता है । उसकी सदस्यता प्रबन्धसमिति के 2/3 सदस्यों की सहमति से तय होगी । उसको संस्था में पद लाभ चकीय कम में अपने नम्बर के आधार पर मिलेगी । विशेष परिस्थिति में प्रबन्ध समिति उसके अधिकार (पद) को तय करेगी जिसके लिये 1/2 सदस्यों की सहमति आवश्यक है ।



(य) साधारण सदस्य:-

1. जो सदस्य 20000 रुपये का धन या सम्पत्ति संस्था को दान देंगे वह साधारण सदस्य होंगे ।
2. यह सदस्य प्रतिवर्ष 31 मार्च तक सदस्यता शुल्क रू0 2000 संस्था के नाम अवश्य जमा कर दे तो वह साधारण सदस्य की रेण्ी में आवेगें ।

सत्य-प्रतिलिपि

Signature

निदेशक

पं० दौनराव उपाध्याय नानुति उमिठि
पु० मुंबई २०००

3. इनकी सदस्यता केवल 5 साल तक ही मान्य होगी, 5 वर्ष बाद यदि वह 20000 रु० या इतने की सम्पत्ति पुनः संस्था को देंगे तो पुनः साधारण बन सकेंगे।

साधारण सदस्यों के कार्यक्षेत्र व अधिकार:-

1. इन सदस्यों को संस्था के हित में सहयोग, सुझाव देने का पूरा अधिकार है।
2. जब तक वह सदस्य है तब तक आय व्यय का व्योरा मांगने का अधिकार है। अनियमितता होने पर या कोई भी सुझाव देने पर प्रबंधसमिति में अपनी बात रखी जायेगी जो 2/3 बहुमत से पास होने पर लागू होगी।
3. इनको प्रबंध समिति में न तो वोट देने का अधिकार न किसी पद पर खड़े होने का अधिकार होगा।
4. इन साधारण सदस्य की अपने किसी छात्र छात्रा को केवल 1 बार 10 प्रतिशत छूट पर प्रवेश देने का अधिकार है यशर्त वह योग्यता रखता है।
5. यदि कोई सदस्य आजीवन सदस्य बनना चाहता है तो आजीवन सदस्य की जगह खाली होने पर संस्था के नाम 80 हजार रुपये 5 साल के अन्दर जमा कर दें। पद का लाभ आदि वरिष्ठता सूची के आधार पर मिलेगा। यदि प्रबंधसमिति उसके नाम पर राजी नहीं है तो 2/3 बहुमत होगा पर ही उसका सदस्यता प्रदान की जा सकती।

प्रत्येक आजीवन सम्माननीय व साधारण सदस्य को प्रवेश सम्बन्धी छूट का लाभ 1 वर्ष में छात्रों की सं० का 10 प्रतिशत ही होगा। अधिक सं० की मांग होने पर प्रबंधसमिति ही तय करेगी कि किसके सदस्य को यह सुविधा उस वित्तीय वर्ष में किसे दी जाये।



1. समिति व प्रबंधसमिति का तात्पर्य वे सभी सदस्य जो आजीवन सदस्य की श्रेणी में आते हैं।
2. शिक्षा समिति- साधारण सभी से है।

सदस्यों की योग्यता:-

- (अ) 18 वर्ष की कम आयु के सदस्य को न तो वोट डालने का अधिकार होगा और न ही पदाधिकारी बन सकेंगे। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर प्रतिबन्ध स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- (ब) जो पागल, दीवालिया, अनैतिक अपराध, चोरी, डकैती, भवन से सम्बन्धित दण्ड के भागी न हों।

सदस्यता की समाप्ति:-

मृत्यु, पागल, न्यायालय द्वारा चोरी डकैती अनैतिक अपराध में दण्डित होने व संस्था के नियमों का पालन न करने पर या लगातार 3 वर्ष की बैठक में बिना

सत्य-प्रतिलिपि

प्रो. व. सु. 11
V. A.
N. S.
K. P.

संस्था के सदस्यों की योग्यता:-
उत्तर प्रदेश

प्रो. व. सु. 11
N. S.
K. P.

चुनाव कार्यवाही विधि:-

निर्धारित 5 साल बाद चुने गये पदाधिकारियों का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जायेगा। जब तक चुनाव नहीं होता तब तक समस्त अधिकार निदेशक में निहित होंगे।

प्रत्येक 5 साल बाद माह अप्रैल में एजेण्डा भेजकर प्रबन्धसमिति की मीटिंग करके चुनाव की तिथि निर्धारित की जायेगी। यदि कोई पदाधिकारी अच्छा कार्य करता है और प्रबन्ध समिति के 2/3 सदस्य उसे मानते हैं तो उसका चुनाव नहीं होगा जब तक उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव न आये और कोई संगीन अनियमितता न हो।

चुनाव अधिकारी प्रबन्धसमिति के द्वारा नियुक्त होगा जिसकी संरक्षता में चुनाव किया जायेगा। उसका निर्णय ही मान्य होगा संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सेसाइटी रजि० अधि० की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रबन्ध समिति प्रशासन द्वारा लिये गये जनहित में निर्णय का स्वागत करेगी तथा उसके लागू करने की पूरी कोशिश करेगी। संस्था के कोष को किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट ऑफिस में उपनिदेशक एवं कोषाध्यक्ष संयुक्त रूप से समिति/संस्था के नाम अपने हस्ताक्षरों से खाता खुलवाकर संचालित करेंगे।

प्रवेश व डिग्री वितरण तथा शासन द्वारा लिये गये निर्णय में प्रबन्धसमिति उचित निर्णय लेगी।

पदाधिकारियों का चुनाव प्रबन्धसमिति द्वारा प्रत्येक 5 साल में होगा। जिसका स्थानसंस्थान या मुख्यालय पर होगा।

जो सदस्य अथवा व्यक्ति 25000 से अधिक धन संस्था को देंगे उनके नाम या उनके बताये नाम से संस्था में उतनी ही लागत के भवन, हाल, रोड का नाम रखा जा सकता है इसे प्रबन्धकारिणी तय करेगी। संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति का होगा। संस्था द्वारा अर्जित लाभ का कितना प्रतिशत संस्था के विकास अथवा अन्य नई योजनाओं में खर्च होगा, यह प्रबन्धकारिणी अपनी वार्षिक बैठक में प्रतिवर्ष तय करेगी। संस्था का आडिट प्रतिवर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

संस्था में हानि की दशा में पूरा दायित्व सभी संरक्षक, आजीवन, सम्माननीय व नामित सदस्यों का होगा। जिसको प्रबन्धकारिणी की बैठक में तय किया जायेगा। विद्यालय के हित में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक या अन्य किसी से ऋण लेना व वापिस देना निदेशक के हाथ में होगा। लेकिन इसकी समीक्षा प्रबन्ध कार्य कारिणी की बैठक में की जायेगी। संस्था का खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जायेगा खाते का संचालन कोषाध्यक्ष व उपनिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

सत्य-प्रतिलिपि



प्रमुख
Vik
Rk
Kk

वरिष्ठ सचिव
संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख
संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख

Handwritten signature
संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख
संस्था प्रमुख, संस्था प्रमुख

प्रतिबन्ध

- (क) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (ख) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- (ग) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तरप्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (घ) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली/काउन्सिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होता है तो उक्त परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जाएगी।
- (ङ) संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिए जायेंगे।
- (च) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जाएगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराए जाएंगे।
- (छ) राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किए जायेंगे, संस्था उसका पालन करेगी।
- (ज) उक्त प्रतिबन्धों में पूर्ण शासन की वित्त अनुमति के परिवर्तन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।
- (झ) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जाएगा यदि हों तो कृपया प्रबन्धकारिणी को इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करें कि विद्यालय की विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध क्रम 1 से 9 तक स्वीकार है।



सत्य-प्रतिलिपि

16/12/2018